

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4765
उत्तर देने की तारीख 23.03.2020

असिस्टेंट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों की संख्या

4765. श्री धर्मेन्द्र कश्यप:

श्री गिरीश चन्द्र:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में श्रेणी-वार (यूआर/ओबीसी/एससी/एसटी) असिस्टेंट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों की संख्या कितनी है;
- (ख) वर्ष 2013 से आज की तिथि तक स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम क्या हैं;
- (ग) उक्त नवस्थापित विश्वविद्यालयों में श्रेणी-वार (यूआर/ओबीसी/एससी/एसटी) विद्यार्थियों की संख्या कितनी है; और
- (घ) वर्ष 2020 में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के तहत 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के संबंध में सहायक प्रोफेसरों/प्रोफेसरों की श्रेणी-वार संख्या निम्नानुसार दी गई है-

01.01.2020 के अनुसार

पद की श्रेणी	स्वीकृत संकाय पदों की संख्या			
	अनारक्षित	अ.पि.व	अ.जा.	अ.ज.जा
सहायक प्रोफेसर	5805	2178	1352	696
प्रोफेसर	1660	269	297	133

इस (01.01.2020 के अनुसार)

पद की श्रेणी	स्वीकृत संकाय पदों की संख्या			
	अनारक्षित	अ.पि.व	अ.जा.	अ.ज.जा
सहायक प्रोफेसर	137	44	36	18
प्रोफेसर	39	8	10	5

(ख) और (ग): वर्ष 2013 से आज की तिथि तक के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नाम निम्नानुसार हैं-

- महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय
- आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
- आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय

नए स्थापित विश्वविद्यालयों में वर्ग-वार छात्रों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम	छात्रों की संख्या
----------	--------------------------------	-------------------

		अनारक्षित	अ.पि.व	अ.जा.	अ.ज.जा
1.	महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	468	228	58	16
2.	आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	31	28	20	10
3.	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	17	49	12	44

(घ) उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित कई उच्चतर शैक्षिक संस्थान पहले ही स्थापित कर लिए गए हैं। 12वीं योजना के अनुपालन में, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा अनुमोदित, उच्चतर शिक्षा प्रणाली के समेकन पर जोर दिया गया है। नए संस्थानों की स्थापना के स्थान पर मुख्यतया मौजूदा संस्थानों की क्षमता बढ़ा कर विस्तार किया जाना है। इसके अतिरिक्त "शिक्षा" एक समवर्ती विषय होने के कारण राज्य सरकारें भी विभिन्न पहल कर रही हैं।
